कितना रेवन्यू में फर्क पड़ा और मोटे तौर से कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ध्यान में नहीं थीं और आडिट ने उनको उसके ध्यान में लाया ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : अंडर एसेसमेंट के केसिस सन 1965 में 10560, 1966 में 9141 और 1967 में 9880 थे । ओवर एसेसमेंट के 1965 में 1283, 1966 में 1408 और 1967 में 2014 थे । इसमें अंडर एसेसमेंट की कुल राशि 1965 में 4 करोड़ 39 लाख था, 1966 में 8 करोड़, 64 लाख थी और 1967 में 7 करोड़ 41 लाख थी । कितनी राशि इसमें से रिकवर हुई ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : दूसरे पार्ट का जवाब नहीं दिया गया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ध्यान में नहीं थीं और आडिट ने उनको उसके ध्यान में लाया ।

**अध्यक्ष महोदय** : नैक्सट क्वेश्चन ।

**Foreign Investment in Fertiliser Industry**

*663. **Shri Madhu Limaye:**
**Shri S. M. Banerjee:**
**Shri George Fernandes:**
**Dr. Ram Manohar Lohia:**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have seen reports in the Christian Science Monitor and other foreign papers that despite the concessions to foreign capital and the extentions of the time-limit, foreign enterprise was not likely to be attracted to India on a big scale;

(b) if so, whether the report is true; and

(c) the concrete steps taken to step up indigenous production of fertilisers?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah)**: (a) Government have seen a report in the Christian Science Monitor of the 4th April, 1967, to the effect, in brief, that "a group of American Oil and Chemical Companies now seems to have rejected a series of concessions" granted by the Government of India to attract investment in the fertiliser industry.

(b) It is naturally not possible to classify such a report as true or otherwise. But some oil and chemical companies have continued to evince interest in our fertiliser developments.

(c) Apart from the projects which will go into production during this year, viz. Namrup and Gorakhpur, in the public sector, and Visakhapatnam and Ennore Expansion in the private sector, additional fertiliser factories are being built or have been approved at Durgapur, Cochin, Madras, Barauni, Namrup and Trombay in the public sector. New fertiliser factories in the private sector have been approved at Kota, Kanpur, Goa, Mangalore and Haldia and in Gujarat. These when completed together, with the existing capacity, will total 2.82 million tonnes of Nitrogen capacity. Government has also taken steps to develop indigenous design, engineering and fabrication capacity so as to achieve greater self-reliance in this industry.

**श्री मधु लिमये** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि **क्रिस्चिएन साइंस मानिटर** की रपट सही है या गलत, इसके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ अमरीकी फर्मों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी अभी नई फर्टीलाइजर नीति घोषित होने के पश्चात यह दिलचस्पी दिखाई गई है या वे पहले से यह दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकला है । क्या यह सही है कि वे इन्तजार कर रहे हैं कि अगर

और दबाव डाला जायेगा, तो यह सरकार झुक जायेगी और उनको नई रियायतें देगी ?

**योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता)** : एक साल ख़त्म होने के बाद उस पीरियड को चन्द महीनों के लिये बढ़ाने की बात जब इस सदन के सामने रखी गई थी, तब यह बताया गया था कि कई कम्पनीज़ के साथ हमारी बातचीत चल रही है । उस वक्त मैंने सात-आठ कम्पनियों के नाम दिये थे । उनके साथ अभी भी बातचीत चल रही है । उनमें से कुछ लोगों ने लैटर्ज़ आफ़ इन्टेन्ट निकाले हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि साल ख़त्म होने तक उनमें से बहुत से इंडस्ट्रियल लाइसेंस निकाल पायेंगे । हमारा ख़याल है कि कुछ नये लोग आयेंगे । अभी तक कुछ ख़तो-किताबत हो रही है और कोई कन्क्रीट प्रोपोज़ल्ज़ हमारे सामने नहीं आये हैं । अगर वे आयेंगे, तो हम उन के बारे में विचार करने के लिये तैयार होंगे । जैसा कि जवाब में बताया गया है, अभी तक जो कुछ कदम उठाये गये हैं, उनको मद्दे-नज़र रखते हुए हमारी यह उम्मीद है कि हम 28 लाख टन नाइट्रोजनस फ़र्टीलाइज़र की कैपेसिटी पैदा कर पायेंगे । अभी कोई नये कनसेशन्ज़ की मांग नहीं हुई है और उनको देने का सवाल नहीं उठता है ।

**श्री मधु लिमये** : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी को जानकारी में यह बात आई है कि बम्बई में फ़र्टीलाइज़र का जो कारख़ाना है, उसकी बुनियाद में और उसमें जो यंत्र आदि लगाये गये हैं, उनमें बहुत बड़े दोष हैं और उसके फलस्वरूप उसमें पूरी पैदावार नहीं हो पायेगी और उसी तरह की शिकायतें केरल में आलवेई के कारख़ाने के बारे में भी हैं; यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने इसकी जांच की है और जो दोषी लोग हैं, उनको कोई सज़ा देने का प्रबन्ध किया है ?

**श्री अशोक मेहता** : जहां तक केरल के कारख़ाने का सवाल है, वहां की जो मुसीबतें हैं, वे दूसरे किस्म की हैं—वे प्लांट की मुसीबतें नहीं हैं । जहां तक ट्राम्बे के कारख़ाने का सवाल है, यह सही है कि उसके प्लांट में कई कमज़ोरियां और ग़लतियां हैं और उसके बारे में प्लांट सप्लाई करने वालों के साथ बातचीत चल रही है ।उन्होंने एक से ज्यादा दफ़ा आ कर उन ग़लतियों और कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश की है । हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले चन्द दिनों में इसके बारे में एक या दूसरी तरफ़ फैसला किया जायेगा । लेकिन हम को डर लगता है कि वहां पर जो प्रासेस लगाया गया है, उसमें तब्दीली करना ज़रूरी होगा ।

**श्री मधु लिमये** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अधूरा उत्तर आया है । मैंने पूछा था कि इस तरह के यंत्र मंगाने में या ग़लत ढंग से बुनियाद डालने में जिन लोगों का दोष पाया गया है, क्या उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही हुई है और अगर वे ठेकेदार हैं, तो क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही की गई है ।

**श्री अशोक मेहता** : मैंने जवाब दे दिया है कि एक्विपमेंट सप्लाई करने वाले एक से ज्यादा दफ़ा आये हैं लेकिन अभी तक आखिरी फ़ैसला नहीं हुआ है कि ये डिफेक्ट्स रीमूव हो सकते हैं या नहीं । हमारा ख़याल है कि ये डिफेक्ट्स इनहेरेंट हैं, जब कि कन्ट्रेक्टर्ज़ और एक्विपमेंट सप्लायर्ज़ का कहना है कि नहीं यह मेनटेनस की ग़लती की वजह से या किसी दूसरे सबब से कमज़ोरी है । जब तक इस मामले का फ़ैसला न हो, तब तक कोई कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठ सकता है ।

**श्री मधु लिमये** : मैं अधिकारियों के बारे में पूछ रहा हूं । मैंने विदेशी सप्लायर्ज़ के बारे में नहीं पूछा है ।

**श्री अशोक मेहता** : जब तक इस बारे में फ़ैसला नहीं हो जाता है, तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि कौन दोषी है और उसके ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मधु लिमये : इस में कितने ही साल हो गये हैं । बर्बाद करो जनता का पैसा ।

**Shri Asoka Mehta:** Sir, I object to this kind of remarks. When I am answering every single question, I do not understand why this kind of *obiter dicta* should be given.

श्री मधु लिमये : उसमें क्या ग़लत है ? हमारी राय है कि आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री मु० अ० खां : राय देने वाले आप कौन हैं ? हमारी राय है कि आप बकवास करते हैं, हमारी राय है कि आप बकते हैं ।

**Shri S. M. Banerjee:** Sir, that hon. Member, who is an emblem of anger, has said:

"आप बकवास करते हैं"

श्री मु० अ० खां : आप लोगों ने पार्लियामेंट को मार्केट बना रखा है । आप को इसकी डिग्निटी और डेकोरम का ख़याल नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप बदतमीज, हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि जब कभी मैं अपने भूतपूर्व सहयोगी से, जो हमारे नेता रहे हैं, कोई सवाल पूछता हूं, तो वह एक-दम गुस्से हो जाते हैं ? आप उनके दिमाग़ को एयर-कन्डीशनर में रखिये ताकि वह ज़रा ठंडा हो जाय । उनके दिमाग़ के लिये एयर-कन्डीशनिंग की ज़रूरत है।

**Mr. Speaker:** We need not go into the reason, whatever be the reason.

**Shri Rajaram:** This is an SSP-PSP trouble.

**An hon. Member:** No insinuations please.

**Shri Hem Barua:** Sir, it is absolutely wrong. When the hon. Member says that this is an SSP-PSP trouble, he is entirely wrong. We do not acknowledge Shri Asoka Mehta as our leader.

**An hon. Member:** He is a renegade.

**Mr. Speaker:** We are not discussing SSP-PSP relations. We are now in the Question Hour in the Parliament of India.

श्री स० मो० बनर्जी : यह देखा गया है कि फ़र्टलाइज़र के जितने नये नये कारख़ाने कायम होते जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है या उत्पादन बढ़ रहा है, उतने ही फ़र्टलाइज़र के दाम बढ़ते जा रहे हैं और किसान को सही दामों पर या रीज़नेबल प्राइस पर फ़र्टलाइज़र नहीं मिलता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा इन्तज़ाम किया जायेगा कि किसान को फ़र्टलाइज़र उचित और सस्ते दाम पर मिले और क्या गवर्नमेंट फ़र्टलाइज़र की प्राइस के बारे में कोई फ़ैसला ले रही है ।

**Shri Asoka Mehta:** As far as our current capacity is concerned, it is only 585 thousand tonnes, but even that capacity is not being fully utilised. Steps are being taken to see that this capacity is fully utilised. In 1967-68 we will add to that capacity 309,000 tonnes and so on and so forth year after year. The plants that were set up in the past were small plants based upon older technology. The new plants that are being set up are much bigger plants based on modern technology. We are confident that the cost of production and therefore the prices of fertilisers produced by the new technology and by the bigger plants will be much lower than the costs that we have to pay for fertiliser that is being produced by the older, smaller and somewhat out-of-date plants.

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने मूल जवाब में बताया है कि निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में कारख़ानों को बढ़ाने का काम चल रहा है ।

क्या वह इस बात का खुलासा करेंगे कि अमरीका से को-आपरेटिव फ़र्टीलाइजर कारखानों के कोई प्रतिनिधि अप्रैल महीने में सरकार से बात करने के लिये यहां आये, उनके साथ बातचीत का क्या नतीजा हुआ और इस वक्त, आज अभी को-आपरेटिव संस्थाओं के जो प्रतिनिधि दिल्ली या हिन्दुस्तान आये हैं उनके साथ किस ढंग की बातचीत चल रही है, को-आपरेटिव क्षेत्र में कितनी पूंजी लगा कर फ़र्टिलाइजर का कारखाना लगाने की योजना है और उसकी कैपेसिटी क्या रहने वाली है ?

श्री अशोक मेहता : को-आपरेटिव लीग की तरफ़ से कुछ लोग आये थे । उनकी हिन्दुस्तान के को-आपरेटिव वालों से और सरकार से बातचीत हुई है । वह टीम वापिस अमरीका गई है और वहां से उनकी तरफ़ से बाकायदा प्रोपोजल्ज आयेंगी । हम उम्मीद रखते हैं कि इस बारे में एक प्राजेक्ट रिपोर्ट बनाई जायेगी और कम से कम एक फ़र्टिलाइजर प्लांट को-आपरेटिव सैक्टर में डालने की हमारी ख्वाहिश और कोशिश है ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का साफ जवाब नहीं मिला । मैंने यह पूछा कि क्या इस वक्त कोआपरेटिव संस्थाओं के कोई भी प्रतिनिधि हिन्दुस्तान आये हैं और सरकार से बातचीत चला रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : मैंने जवाब दिया वह आये, गये हैं, फिर आने वाले हैं । उनके प्रोपोजल्स तैयार करने की बात है ।

**Shri R. Barua:** May I know whether negotiations with Kuwait in regard to the establishment of fertiliser plant have proceeded well and, if so, whether it is going to improve our position with regard to sulphur scarcity?

**Shri Asoka Mehta:** As far as sulphur is concerned, the hon. Member is right that the position continues to cause anxiety. We are, therefore, trying to see to what extent we can use pyrites to produce sulphuric acid. But that will take some time. In the meantime, the short supply of sulphur continues to cause anxiety.

**Shri Umanath:** May I know whether the foreign interests are insisting on a condition that we must accept ammonia-based plants in the place of naphtha-based plants? This means that in the case of ammonia-based plants, we will have to depend on the import of ammonia which will tell upon our foreign exchange resources whereas in the case of naphtha-based plants, there is internal production of naphtha. I would like to know whether the foreign interests are insisting on our accepting ammonia-based plants as a condition for them to come here and whether Government will give this House an assurance that they will never accept condition of accepting ammonia-based plants to be established here.

**Shri Asoka Mehta:** Firstly, there are certain cases in which proposals have been put forward that liquid ammonia be allowed to be imported for a period of time. There is a suggestion that the import of liquid ammonia will be simultaneously tied with the assured supply of sulphur because of the acute shortage of sulphur where this kind of proposals are being made. These proposals are being studied by the Government. It is not possible for me to give any kind of an assurance on the subject till the matter has been closely studied.

**Shri Vasudevan Nair:** That is another surrender.

**Shri Asoka Mehta:** This is a matter which is being studied by Government. The hon. Member is free to reach any conclusion he likes. I will come with concerete details after Government has studied it. He has asked me to give an assurance when I am studying the matter. Until my study is over and I have got a clearance from Government also, it is not possible to give an assurance.

**Shri Ranga:** May I know whether this Ministry have ascertained to what extent the prices of fertilisers have gone up as a result of the decision taken in the Budget to give up the subsidy?

**Shri Asoka Mehta:** My Ministry is concerned with producing fertiliser. The distribution is with the Ministry of Agriculture.

**श्री सीताराम केसरी** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बिना विदेशी मूल्य के अपनी ताकत पर हम यह फर्टिलाइजर फैक्ट्री बिठा सकते हैं या नहीं और यह जो हमारे यहां फैक्ट्री लगी हुई है उसकी उत्पत्ति आज तक कितनी हुई और यह अपनी ताकत पर बिठाने के बाद हम उतनी उपत्ति कर सकते हैं या नहीं ?

**श्री अशोक मेहता** : आज जो मैंने बताया कि आज अभी वहां कैपेसिटी 5 लाख 85 हजार टन की है उसमें से करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में है । मैंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि 2.8 तक हमारी कैपेसिटीज बढ़ेंगी उसमें 15 लाख से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में रहेगा और इस वक्त भी कई प्लांट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं । कुछ नये बन रहे हैं जो पूरे हो जायेंगे और नये चार शुरू करने का काम हम ने हाथ में लिया हुआ है ।

**श्री महाराज सिंह भारती** : अध्यक्ष महोदय, जो 28 लाख टन नेत्रजन का हम ने लक्ष्य रखा है जिसे इन्टेन्सिव ऐग्रीकल्चर, पहरी खेती कहते हैं उस के हिसाब से एक टन नेत्रजन अगर एक फसल में रखी जाये तो दस एकड़ के लिए पर्याप्त होत है और फिर चाय बागान वगैरह की भी जरूरत है तो आप का लक्ष्य मालूम पड़ता है कि 3 लाख एकड़ के लिए भी नाकाफी होगा और जरूरत होगी बहुत ज्यादा । साथ में हमारी पोजीशन यह है कि जो हम बिजली से फर्टिलाइजर तैयार करते हैं नांगल फर्टिलाइजर की तरह है वह इतनी बिजली उस में लगती है कि हरयाना और पंजाब में जितनी बिजली खपती है उस से ज्यादा अकेली नागल में खपती है और नेफ्था से जो हम प्लांट बनाने जा रहे हैं उस की यह सीमा है कि जितना हम पेट्रोल तैयार करेंगे उस का जो बाईप्राडक्ट नेफ्था होगा उसी के हिसाब से हम फर्टिलाइजर बना सकेंगे । तो बिजली की कमी है और नेफ्था पैदा होने की सीमा है और आवश्यकता जो लक्ष्य रखा है उस से कम से कम 5 गुनी अधिक है तो इस परिस्थिति में आप किस तरह से प्लांट बनाना चाहते हैं ? किन चीजों से फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं ?

**श्री अशोक मेहता** : जहां तक फर्टिलाइजर कितना मुल्क में तैयार करना है यह सवाल है उस का फैसला या उस की हिदायत हमें ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से और प्लानिंग कमीशन से मिलती है । दोनों ने कहा है कि चौथे प्लान के आखीर तक 24 लाख टन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और दस लाख टन फास्फैटिक फर्टिलाइजर मुल्क में पैदा करना जरूरी है अगर हो सके तो और उन की राय में इतनी पैदावार जो हो सके तो काफी होगी मुल्क के लिए । और दूसरा सवाल पूछा गया एलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत होता है वह प्रोसेस हिन्दुस्तान में अब हम नहीं चला रहे हैं, शायद मैसूर के अन्दर जहां काफी एलेक्ट्रिसिटी है वहां से प्रोपोजल है कि करीब करीब उसी किस्म के प्रोसेस पर फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं । उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं । नेफ्था की कमी होगी तो बाहर से मंगाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ नेफ्था के लिए सारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाना, वह ठीक नहीं होगा । हो सकता है कि एक दो साल के लिए कमी नेफ्था की कमी हो जाय तो वह हम इम्पोर्ट कर लेंगे लेकिन हमारी यह कोशिश है कि

**By 1975, we will be completely self-sufficient in all our requirements.**

**Shrimati Lakshmikanthamma:** Is it a fact that import of fertiliser will cost less in terms of foreign exchange than import of foodgrains and production of fertiliser in our own country will cost less than import of fertilisers, and may I also know whether the Government will concentrate on the production of fertilisers in our country and when we propose to attain self-sufficiency in fertilisers in our country?

**Shri Asoka Mehta:** I have been been answering this question all the time. Firstly, we are doing all that is possible to push ahead with the fertiliser programme and I have said that we hope that, by and large, we will be self-sufficient by the end of the Fourth Plan.

**Shri S. Kandappan:** In view of the long gestation period taken for a fertiliser factory to go into production and in view of the acute shortage with regard to fertiliser availability in Madras, I would like to know when the Madras Refinery will be going into production and, meanwhile, what arrangements are made to meet the requirements of the State.

**Shri Asoka Mehta:** The Madras Refinery will take between two to three years to be completed and side by side the fertiliser plant is also, going ahead.

**Shri S. Kandappan:** Meanwhile, what arrangements are made to meet the requirements of the State?

**Shri Asoka Mehta:** To import, through the Agriculture Ministry,

**Shri S. Kandappan:** You have not supplied even half of the requirements.....

**Shri Asoka Mehta:** He must take it up with the Agriculture Ministry and not with me.

**Shri A. V. Patil:** May I know whether it is a fact that due to shortage of chemical fertilisers, many factories are coming up producing manual mixtures and these menual mixtures are nothing more than dusts mixed with some unknown ingredients?

**An hon. Member:** Adulterated fertiliser.

**Shri Asoka Mehta:** I am not aware.

**श्री बोल्हू प्रसाद** : अध्यक्ष होदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विदेशी सहायता से गोरखपुर में खाद कारखाना का निर्माण हुआ है । वह अप्रैल, 1967 तक चालू हो जाने वाला था लेकिन जून का महीना चल रहा है अभी तक चालू न हो सका, उस की क्या वजह है और जो वह अब तक चालू नहीं हुआ उस में क्या कुछ भ्रष्टाचार का भी मामला कुछ है, ऐसी शिकायत मंत्री जी को मिली है ?

**श्री अशोक मेहता** : गोरखपुर का कारखाना हम उम्मीद रखते है कि जुलाई में ट्रायल शुरू होगा । और सितम्बर से प्रोडक्शन शुरू हो जायगा । और भ्रष्टाचार का कुछ मामला है तो हमारे पास भेज दीजिए । मैं उस को देखूंगा ।

**Shri Shankaranand:** In view of the shortage of fertiliser, has the Government any definite proposal to set up a fertiliser factory in mysore State?

**Shri Asoka Mehta:** There is a proposal to set up a fertiliser plant at Mangalore.

**Shri Hem Barua:** Just now, the hon. Minister has said that it is proposed to set up some six or seven fertiliser plants in this country, although we know that most of these were sanctioned before the 31st March, 1966. In the context of that, may I know how many of these proposed fertiliser plants are in collaboration with foreign capital and how many are in collaboration with indigenous capital? May I know whether it is also a fact that the Birla have approached this Government with a request to allow them to set up a fertiliser plant and if so, Government's reaction to that proposal?

**Shri Asoka Mehta:** With the exception of one plant, namely that at Haldia, where the proposals have been put forward by Philips Petroleum Co., in the case of all other plants, there are Indian collaborators also, and it is the Indian collaborators who have mostly been negotiating with us. There are some fertiliser plants in the private sector where there is no foreign collaboration whatsoever. There are others where there is foreign collaboration but where the initiative has been taken by Indians. As I have said, there is only one proposal from Philips Petroleum Co. where the intiative has been taken by the foreigners. As far as Birlas are concerned, they have already got an industrial licence for setting up a fertiliser plant at Goa in collaboration with Armour Co. of America. The Birlas have recently come forward with proposals to set up a fertiliser plant at Mirzapur in collaboration with Kaisers, and that matter is under examination.

**श्री चण्द्रिका प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के प्लान्ट की कैपेसिटी कितनी है तथा वहां पर जिन लोगों की जमीनें ली गई थीं, उन को इस कारखाने में नौकरियां देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वैसा नहीं हुआ ?

**श्री अशोक मेहता** : उस प्लान्ट की कैपेसिटी 80 हजार टन प्रतिवर्ष है । जहां तक वहां की जमीन के बारे में समस्या है, मेम्बर साहब मुझे लिख कर भेजेंगे तो मैं देख लूंगा ।

**Wealth of the Late Nizam of Hyderabad**

+

***664. Shri S. M. Banerjee:**
**Shri Madhu Limaye:**
**Shri M. R. Krishna:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made of the accumulated wealth and jewellery of the late Nizam of Hyderabad after his death;

(b) whether it is a fact that some of the jewellery has been smuggled out, to other countries; and

(c) if so, the steps taken by Government to have an account of the total wealth and jewellery of the late Nizam?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant):** (a) No assessment to wealth-tax or estate duty has been made in respect of the wealth and jewellery of the late Nizam after his death.

(b) According to uptodate information no jewellery has been smuggled out of the country.

(c) Does not arise.

**Shri S. M. Banerjee:** From the answer it appears that even after the death of the Nizam of Hyderabad, no assessment was made. May I know whether there is any record in the possession of Government to show what wealth he had, whether movable or immovable, with him before his death?

**Shri K. C. Pant:** The Nizam died, I think, on the 24th February, 1967. It should not cause the hon. Member surprise that no assessment has been made during the last few months. That is all that I have said in the answer.

So far as the list of movable and immovable property of the Nizam is concerned, under an agreement with the Government of India in 950, the Nizam furnished a list of his movable and immovable property which after being vetted by the Government of Hyderabad was accepted by the Government of India.

**Shri Surendranath Dwivedy:** What is the amount? What was the assessment that was made before his death?

**Shri Ranga:** First, the hon. Minister said that there was no assessment; then he has said that an assessment was made which was vetted by the